

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 58/2013/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त-बी,कोटा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स यतीश कुमार एण्ड कम्पनी

भामाशाह मण्डी, कोटा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित:

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एम.एल.पाटोदी

अभिभाषक

अपलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 15.01.2014

निर्णय

यह संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1691/2007/कोटा में पारित निर्णय 15.04.2013 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत एस टी 17 घोषणा पत्रों की सूची में मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स, कोटा द्वारा जारी एस टी-17 घोषणा पत्र संख्या 23455/25 रु. 21,30,340/-का भी प्रस्तुत किया गया था। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बांरा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने जांच पर पाया कि उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त व्यवसायी के एस टी-17 घोषणा पत्र की सीरीज के घोषणा पत्र निरस्त कर दिये गये थे लेकिन प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र उसी सीरीज का होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 16.2.2005 पारित कर उक्त घोषणा पत्र को अस्वीकार कर कर रु. 85,214/- एवं ब्याज रु. 32,381/-आरोपित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(अपील्स)वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर उन्होंने विचार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स, नई धानमण्डी, कोटा द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम जारी किये गये एसटी-17 घोषणा पत्र के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में यदि उनके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम,1995 के नियम 23 (16) एवं (20) में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निष्पादन किया गया है, तो प्रत्यर्थी व्यवहारी पर नियमानुसार कर एवं ब्याज आरोपित किया जावे अन्यथा इन्हें स्वीकार किया जाकर आरोपित अतिरिक्त कर व ब्याज समाप्त किया जावे। अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.02.2007 को यथावत रखते हुए राजस्थान की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गई।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने राजस्थान कर बोर्ड के माननीय सदस्य श्री ओ.पी.सहारण द्वारा अपील संख्या 1742 / 2007 / कोटा निर्णय दिनांक 30.01.2009 एवं अपील संख्या 1955 / 2007 / कोटा निर्णय दिनांक 20.01.2011 को उद्धृत करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2013 का समर्थन करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। संशोधन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के समय प्रस्तुत बहस प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जा सकता है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों। कर बोर्ड की एकलपीठ पारित द्वारा निर्णय दिनांक 15.04.2013 में रिकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरणों के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) के प्रकरण में मत प्रतिपारित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

“The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a

power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 253 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of

rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-

“8.The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.

An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf.”

In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held thagt such a power of rectification could onlybe exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the contextst of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.

Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नहीं जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य